ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 279-281**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

बिहार में सामाजिक विकास योजनाः एक मूल्यांकन

पुतुल कुमारी
शोध अध्येत्री– समाजशास्त्र, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना (बिहार) भारत

Received-12.03.2025 **Revised-19.03.2025** **Accepted-23.03.2025** **E-mail : advputulkumari @gmail.com**

सारांशः बिहार में सामाजिक विकास योजनाओं का मूल्यांकन करते समय यह समझना ज़रूरी है कि राज्य में केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर कई सामाजिक योजनाएँ आज भी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लागू हैं। यहाँ एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है :

कुंजीभूत शब्द– सामाजिक विकास योजना, मूल्यांकन, गरीबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा, महिला–बाल विकास, कौशल विकास ग्रामीण सशक्तिकरण।

1. सामाजिक विकास योजनाओं का परिचय – बिहार में सामाजिक विकास का मतलब गरीबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा, महिला–बाल विकास, कौशल विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं से है। इनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यक्रम दोनों शामिल हैं।

प्रमुख योजनाएँ – SAKSHAM (Social Protection Project)

- सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यह कार्यक्रम संचालित है।
- इसका लक्ष्य गरीब, वरिष्ठ नागरिक, विधवा, विकलांग और कमजोर परिवारों को सेवाएं देना है।
- इसे ॅवतसक ठंदा समर्थन भी मिला है ताकि राज्य के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :

- विधवा महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लिए पेंशन प्रदान करती है।
- यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से अलग राज्य स्तर पर लागू किया गया कार्यक्रम है।

कौशल विकास और युवा योजनाएँ :

- "कुशल युवा कार्यक्रम", छात्र क्रेडिट कार्ड और अन्य युवा सहायता योजनाएँ युवाओं को रोजगार–उन्मुख प्रशिक्षण देती हैं।
- ये योजनाएँ शिक्षा और कौशल प्राप्ति को बढ़ावा देती हैं।

JEEViKA – ग्रामीण आजीविका परियोजना :

- ग्रामीण गरीबों के सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए "दीदी की रसोई" जैसी पहलें भी शामिल हैं।
- यह ग्रामीण गरीबों की आय और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है।

योजनाएँ जैसे MGNREGA, IAY, PDS आदि :

- मिहनत गारंटी (MGNREGA), आवास सहायता (IAY) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी केंद्र–राज्य संयुक्त योजनाओं से ग्रामीण गरीबी और आजीविका सुरक्षा का प्रयास होता रहा है।

2. योजनाओं का मूल्यांकन– सकारात्मक प्रभावः गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा : राज्य सरकार पेंशन, रोजगार और जीवन–निर्वाह सहायता से गरीब और कमजोर वर्ग की बेसिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। साथ ही, बैंक हस्तांतरण और आधारभूत सेवा की पहुँच से इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँच रहा है।

महिला सशक्तिकरण : महिलाओं के लिए पेंशन, स्वयं सहायता भत्ता और रोजगार के अवसर सृजन में योजनाएँ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उदाहरण के तौर पर JEEViKA के अंतर्गत महिलाओं को आजीविका अवसर, प्रशिक्षण, आत्मनिर्भरता मिल रही है।

कौशल एवं रोजगारः कुशल युवा कार्यक्रम जैसे कौशल पहल युवाओं को नौकरी या स्वरोजगार में मदद देने के उद्देश्य से हैं, जो दीर्घकालिक रोजगार क्षमता को बढ़ाते हैं।

चुनौतियाँ और सीमाएँ – कवर बढ़ाने की ज़रूरत : हाल के अध्ययन बताते हैं कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा आवास, रोजगार और पेंशन कार्यक्रमों का कवरेज अभी भी बहुत सीमित है, और लाखों गरीब अभी भी बाहर हैं।

प्रभाव का असमान वितरणः शहरी और ग्रामीण, विभिन सामाजिक समूहों में लाभ वितरण में असमानता अक्सर देखने को मिलती हैः उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की पहुँच कम होने का मुद्दा। ऐसे असंतुलन को भविष्य में ढीला करने की ज़रूरत है।

प्रबंधकीय कमजोरियाँ : योजनाओं के कार्यान्वयन में रिपोर्टिंग, निगरानी और पारदर्शिता अभी भी चुनौतियाँ हैं। प्रखंड स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें अब शुरू की जा रही हैं, पर नीतिगत सुधार अभी भी जरूरी हैं।

3. समग्र निष्कर्ष – बिहार में सामाजिक विकास योजनाएँ गरीब, महिला, विकलांग और युवा वर्ग के लिए सकारात्मक कदम हैं और कई मामलों में जीवन स्तर उन्नत कर रही हैं, लेकिन व्यापक पहुँच, निगरानी, पारदर्शिता और लाभार्थियों की पहचान में सुधार जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

सिफारिशें –

- योजनाओं का कवर और दायरा बढ़ाया जाए।
- पारदर्शिता और डिजिटल मॉनिटरिंग में सुधार हो।
- सामाजिक–आर्थिक रिपोर्टिंग और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।

बिहार की "सात निश्चय– 2" योजना और JEEViKA (जीविका) परियोजना का विस्तृत विवरण और उनका सामाजिक विकास पर प्रभाव दिया गया हैः जिससे आप समझ सकें कि ये योजनाएँ किस प्रकार राज्य में गरीबी, बेरोज़गारी, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका जैसे मुद्दों पर काम कर रही हैं।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

1. सात निश्चय, 2 योजना – उद्देश्य और मुख्य घटक – "सात निश्चय– 2" (Saat Nishchay– 2) बिहार सरकार का एक व्यापक विकास कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य समग्र सामाजिक–आर्थिक उन्नति है। यह 2020 में शुरू किया गया था और इसके तहत कई क्षेत्रों में योजनाओं को एकीकृत कर राज्य–व्यापी विकास सुनिश्चित करने की कोशिश होती है।

मुख्य उद्देश्य –

- सभी वर्गों के लिए रोज़गार, शिक्षा और कौशल विकास
- महिला सशक्तिकरण
- कृषि एवं सिंचाई से जुड़े समर्थन
- ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढाँचे का विकास
- स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार

मुख्य घटक (Themes) –

1. **युवा शक्ति – कौशल और रोजगार :** बेरोज़गार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्ति के अवसर देना।
2. **सशक्त महिला – आर्थिक सशक्तिकरण :** महिलाएँ शिक्षा, स्वरोज़गार और उद्यमिता के ज़रिए सशक्त बनें, इसके लिए अनुदान/कर्ज इनसेंटिव देने का लक्ष्य है।
3. **अच्छी कृषि, सिंचाई व उत्पादकता :** हर खेत तक पानी और कृषि सम्बंधित सपोर्ट बढ़ाना।
4. **स्वच्छ, समृद्ध गांव और शहर :** स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, पेय जल एवं शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं का विस्तार।
5. **सुलभ कनेक्टिविटी :** बेहतर ग्रामीण और शहरी सड़क/संवाद सुविधाएँ।
6. **सामाजिक स्वास्थ्य सुविधाएँ :** स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

इस योजना के तहत सरकारी आंकड़ों के अनुसार दस लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी और अन्य रोजगार के अवसर प्रदान किए जा चुके हैं, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री ने भी किया है।

2. **JEEViKA (जीविका) परियोजना – ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तिकरण –** JEEViKA बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने वाली सबसे बड़ी आजीविका मिशन परियोजनाओं में से है। इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिंक्ड विभिन्न समूहों (SHGs) के माध्यम से आजीविका तथा सामाजिक सुदृढ़ता स्थापित करना है।

मुख्य विशेषताएँ – महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) : करीब 90 लाख परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया, जिनसे सामूहिक बचत, ऋण, बाजार पहुँच जैसी सुविधाएँ मिलीं।

बैंकिंग और वित्तीय पहुँच : SHGs को बैंक ऋण में मदद मिली – अब तक रु10650 करोड़ से ज्यादा का बैंक क्रेडिट इन समूहों ने लिया है।

स्थानीय उद्यमियों की संख्या : लगभग 6.48 लाख महिलाएँ ग्रामीण बिहार में उद्यमी बन चुकी हैं, जिनके व्यवसाय से आय बढ़ी।

सतत् आजीविका योजना के प्रभाव : एक अलग पहल के तहत 95,000 से अधिक गरीब परिवारों को अत्यंत गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली।

Jeevika Nidhi (सहकारी संघ) : बिहार सरकार ने Jeevika Nidhi Sahakari Sangh Ltd शुरू किया है, तॉकि महिलाएँ कम ब्याज पर ऋण ले सकें और पारंपरिक महँगे माइक्रोफाइनेंस पर निर्भरता कम हो।

3. सामाजिक प्रभाव और मूल्यांकन –

सकारात्मक परिणाम : रोज़गार और आत्मनिर्भरता : JEEViKA और सात निश्चय–2 के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिली है।

गरीबी उन्मूलन : सतत् आजीविका योजना से हजारों परिवारों को गरीबी से निकाला गया।

महिला सशक्तिकरण : महिलाओं ने SHGs के माध्यम से न सिर्फ आय अर्जित की बल्कि परिवार और समुदाय में निर्णय क्षमता भी बढ़ी।

चुनौतियाँ (जिन पर सुधार की आवश्यकता) –

लाभार्थियों की पहचान तथा पहुंच : कई मामलों में ज़मीनी स्तर की पहचान और योजना लाभार्थियों तक पहुँचना अभी भी चुनौतीपूर्ण है – जैसे भ्रष्टाचार, स्थानीय प्रशासनिक बाधाएँ और जागरूकता की कमी।

प्रभाव का असमान वितरण : कुछ योजनाओं का लाभ एक समान हर जिले या समुदाय में नहीं पहुँच पाया है कृ जैसे ग्रामीण बनाम शहरी या समाज के पिछड़े वर्गों में।

4. **उदाहरण: नौकरियों और भत्ता योजनाएँ –**

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना : अब स्नातक बेरोज़गार युवक – युवतियों को रु1000 प्रति माह तक भत्ता 2 साल तक दिया जा रहा है, ताकि उन्हें तैयारी या कौशल प्रशिक्षण में सहायता मिले।

लक्ष्य : 2020–25 के दौरान लगभग 10 लाख सरकारी नौकरी और 39 लाख रोजगार अवसर प्रदान कर लिए हैं और अब 2025–30 में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

समग्र निष्कर्ष – सात निश्चय–2 योजना और JEEViKA एक साथ बिहार में सामाजिक विकास की दिशा में बड़े पैमाने पर योगदान दे रहे हैं।

JEEViKA महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करता है, सात निश्चय– 2 युवाओं, रोजगार सृजन, कौशल विकास, कृषि, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाता है।

अतः इन योजनाओं के कारण गरीबी उन्मूलन, आजीविका समर्थन और सामाजिक गतिशीलता में सुधार के कई सकारात्मक संकेत मिलते हैं, हालांकि ज़मीनी कार्यान्वयन में अभी भी चुनौतियाँ हैं।

*****